+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी गुरूवार विक्रम संवत् 2079। 23 जून 2022

6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

JKDESIGN 8369994118

इस सर्किट के तहत राज्य में बन रही हैं पांच सड़कें

बुद्ध सर्किट की सभी सड़कों पर 2025 तक शुरू होगा आवागमन

योजना

संवाददाता ▸ पटना

राज्य में बन रहे बुद्ध सर्किट की सभी सड़कों से होकर 2025 तक आवागमन शुरू होने की संभावना है. इस सर्किट के तहत मुख्य पांच सड़कों का निर्माण हो रहा है. इनमें पटना-गया-डोभी रोड, आमस-दरभंगा एक्सप्रेस वे, पटना रिंग रोड में रामनगर से कच्ची दरगाह, दरियापुर-मनिकपुर-साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क सहित गया-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहारशरीफ सड़क शामिल हैं. इनके माध्यम से राज्य में मौजूद भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा. इससे राज्य में पर्यटन का विकास होगा. फिलहाल राज्य में प्रमुख बुद्ध स्थल बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और केसरिया हैं. इस बुद्ध सर्किट का जुड़ाव उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट से भी होगा. उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट के तहत सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशांबी और कपिलवस्तु मुख्य रूप से जुड़ेंगे.

बुद्ध सर्किट का जुड़ाव उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट से भी होगा

पटना-गया-डोभी फोरलेन एनएच-83 सड़क का निर्माण करीब 127 किमी लंबाई में करीब 1610 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है. वहीं, एनएच-119डी आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण करीब 198 किमी लंबाई में करीब 6927 करोड़ रुपये की लागत से 2024 तक तक पूरा होने की संभावना है. इसके साथ ही करीब 13 किमी की लंबाई में पटना रिंग रोड में रामनगर से कच्ची दरगाह तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए डीपीआर बन रही है. इससे अलग एनएच-139डब्ल्यू दरियापुर-मनिकपुर-साहेबगंज-अरेराज-बेतिया फोरलेन सड़क करीब 167 किमी लंबाई में बनाने के लिए डीपीआर बन रही है. दोनों सड़कों का निर्माण इसी साल शुरू होने और 2025 तक पूरा होने की संभावना है. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग ने करीब 93 किमी लंबाई में फोरलेन गया-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहारशरीफ सड़क एनएच-82 का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना जतायी है.

एनएचएआइ बताये नये पौधारोपण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही : कोर्ट

पटना. पटना हाइकोर्ट ने नारायणपुर - मनिहारी- पूर्णिया हाइवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने एनएचएआइ को यह बताने को कहा कि पौधारोपण के मामले में ग्राम पंचायत के अधिकार और उसकी भूमिका के संबंध में जानकारी देते हुए यह बताएं की नये पौधारोपण के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पूर्व की सुनवाई में एनएचएआइ द्वारा दायर जवाबी हलफनामा दायर कर कहा गया था कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है. पेड़ों को गिराने व ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई तीन फरवरी, 2021 और 23 फरवरी, 2021 को जिला वन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में की गयी थी.

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 23.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए जिलों का हुआ चयन, मोर्थ करेगा निगरानी

जिलों के विकास का रोडमैप तैयार

विशेष

500 करोड़ से ज्यादा के काम की निगरानी सूबे में मोर्थ के पास

13 आकांक्षा, 6 आदिवासी और 16 उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी विकास

- जिलों में विकास का प्रोजेक्ट तय करेगा नेशनल प्लानिंग ग्रुप
- सभी प्रोजेक्ट नेशनल प्लानिंग ग्रुप के सामने करना होगा प्रस्तुत

इन 12 आकांक्षा जिलों में भी विकास

कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर व नवादा।

उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों का भी रोडमैप बना

अरवल, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास और वैशाली।

जिलों में विकास के लिए आठ क्लस्टर

1. डिफेंस कॉरिडोर
2. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर्स
3. फिशिंग शी-फूड क्लस्टर
4. मेगा फूड पार्क्स
5. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम
6. फार्मा एंड मैडिकल कलस्टर
7. स्पेशल इकोनोमिक जोन
8. टेक्सटाइल क्लस्टर

किस जिले में कौन क्लस्टर

- भागलपुर व गया में टेक्सटाइल्स क्लस्टर।
- बेगूसराय व खगड़िया में मेगा फूड पार्क व फिशिंग शीफूड क्लस्टर।
- दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में भी फिशिंग क्लस्टर।
- गया में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम।

छह आदिवासी जिलों में भी होगा विकास का काम

जमुई, बांका, मुजफ्फरपुर, नवादा, गया और औरंगाबाद।

भागलपुर, वरीय संवाददाता। प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार के कई जिलों के विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) को निगरानी करने को कहा है। विभिन्न कटेगरी के लिए चयनित जिलों में विकास का प्रोजेक्ट नेशनल प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) तय करेगा।

केंद्र ने कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा के सभी प्रोजेक्ट मोर्थ के अधीन वाली नेशनल प्लानिंग ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत 12 जिलों को आकांक्षा, 6 जिलों को आदिवासी व 16 जिलों को उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास का खाका तैयार किया गया है। इस संबंध में मोर्थ के अवर सचिव रंजीत कुमार रॉय ने निर्देशों से एनएचएआई समेत तमाम कंस्ट्रक्शन विभागों को पत्र भेजा है।

मोर्थ ने तैयार किया प्रारूप: इसके लिए मोर्थ ने एक प्रारूप तैयार किया है। इसमें स्पॉसरिंग मिनिस्ट्री के नाम, प्रोजेक्ट टाइटल, वर्क लोकेशन, डीपीआर, भूमि-अधिग्रहण स्थिति, प्रोजेक्ट कॉस्ट, कार्यारंभ की अवधि, परियोजना से कितने लोगों को मिलेगा रोजगार के अलावा नजदीकी रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि भरकर मिनिस्ट्री को देना है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 23.06.2022 | पृष्ठ सं० 09

तैयारी | जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है पूरा, 14 हजार करोड़ की परियोजनाओं का टेंडर होना है

इस साल 307 किमी सड़क व पुलों का निर्माण शुरू होगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। इस साल राज्य में 307 किलोमीटर सड़क व पुल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। कुल नौ परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने तैयारी कर ली है। दो-तीन परियोजनाओं का टेंडर इसी महीने जारी होने की संभावना है जबकि बाकी का टेंडर आने वाले दिनों में जारी होगा। 14 हजार करोड़ की जिन परियोजनाओं का टेंडर होना है उसमें पटना से बिहटा एयरपोर्ट जाने के लिए बनने वाली सड़क दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड और पटना रिंग रोड में शामिल गंगा नदी पर बनने वाला शेरपुर-दिघवाड़ा पुल भी है। पिछले दिनों सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की थी। उसमें इन परियोजनाओं पर अविलंब काम शुरू करने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने कहा है कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर एनएचएआई अविलंब टेंडर जारी करे ताकि इसका काम शुरू हो सके। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई को इस बाबत आवश्यक निर्देश दे दिया है। उम्मीद है कि आज-कल में ही नौ में से दो-तीन परियोजनाओं का टेंडर जारी हो जाएगा। जबकि मार्च 2023 तक सभी नौ परियोजनाओं का टेंडर जारी कर लिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार चयनित एजेंसी इन परियोजनाओं पर काम शुरू करेगी। जिन परियोजनाओं का टेंडर होना है, उसपर काम शुरू होने से राज्य के दर्जन भर जिले को प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होगा।

परियोजना	लंबाई	लागत राशि
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड	19.38	3477
आदलवारी-मानिकपुर	40	846.59
मानिकपुर-साहेबगंज	42.80	918.06
साहेबगंज-अरेराज	39.64	833.25
सीवान-मशरख	51.85	1350.75
बहादुरगंज-किशनगंज	23.08	470.31
शेरपुर-दिघवाड़ा गंगा पुल	15	5134
छोरमा-बैरगनिया	37.03	597.71
सहरसा-उमगांव	38.54	605.11

(नोट-राशि करोड़ में और लंबाई किमी में है)

तीन परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी

केंद्र सरकार ने राज्य की तीन परियोजनाओं की औपचारिक मंजूरी दे दी है। अब इन परियोजनाओं का जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। मुजफ्फरपुर से बरौनी के बीच बनने वाली चार लेन सड़क की मंजूरी मिल चुकी है। 116.23 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण पर 3337 करोड़ खर्च होना है। मोकामा से मुंगेर के बीच चार लेन सड़क बननी है। 96 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 4286 करोड़ खर्च होगा। जबकि बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बक्सर से हैदरिया के बीच सड़क का निर्माण होना है। 22.66 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1769 करोड़ खर्च होगा।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 23.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

नई शिक्षा नीति के तहत बदलेगा पढ़ाई का तरीका , खेल-खेल में बच्चे समझेंगे चैप्टर

आईआईटी गांधीनगर मॉडल से होगी छठी से आठवीं तक पढ़ाई

विशेष

■ रिंकू झा

पटना। नई शिक्षा नीति के तहत छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ाई का तरीका बदलने की तैयारी हो रही है। अब छठी से आठवीं तक के सरकारी स्कूल में आईआईटी गांधीनगर के सेंटर ऑफ क्रिवेटिव लर्निंग द्वारा तैयार मॉडल पर पढ़ाई करायी जाएगी।

इस मॉडल को समझने के लिए बिहार से दो शिक्षकों को आईआईटी गांधीनगर का भ्रमण करवाया गया था। इसमें प्राथमिक विद्यालय मितरभगत टोला शाहपुर दानापुर के शिक्षक आकाश आनंद और मध्य विद्यालय गरखा सारण के प्राचार्य अखिलेश्वर प्रताप पांडे शामिल हैं। तीन दिन के इस भ्रमण में दोनों शिक्षकों को खिलौने के माध्यम से विज्ञान और गणित विषय की पढ़ाई गतिविधियों के माध्यम से करवाये जाने की जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा शिक्षकों को मई के अंतिम सप्ताह में भेजा गया था। कोल्ड ड्रिंक की स्टॉ से आवाज (साउंड) के विभिन्न आयाम को समझ सकते हैं। महिला और पुरुष की आवाज कैसे अलग-अलग होती है, इसे एक बार में बच्चे समझ लेंगे। वहीं सर्किल बनाना, सीधी रेखा या त्रिभुज की जानकारी गत्ते के मॉडल से बतायी जाएगी। गेंद के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और धरती को समझना आसान होगा। चांद जिस तरह से धरती की परिक्रमा करता है, उसे गेंद से समझाया जाएगा। जिन चीजों का इस्तेमाल बच्चे अपने खेल में करते हैं, अब उन्हीं चीजों से पढ़ाई करेंगे।

- कागज, स्ट्रॉ, गत्ते से बने दो सौ मॉडल से विज्ञान व गणित की बारीकियां सीखेंगे बच्चे
- मॉडल की विशेषताएं समझने के लिए बिहार से दो शिक्षकों को भेजा गया आईआईटी गांधीनगर

धीरे-धीरे नौवीं से 12वीं कक्षा में भी लागू होगा

इसे अभी छठी से आठवीं तक लागू किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे नौवीं से 12वी तक लागू किया जाएगा। शिक्षक आकाश आनंद ने बताया कि अभी कक्षा किताबों और अंकों पर केंद्रित है, जबकि अब पढ़ाई का तरीका गतिविधि पर आधारित होगा।

बच्चों में रचनात्मक दक्षता का विकास होगा

प्राचार्य अखिलेश्वर प्रताप पांडे ने बताया कि 'लर्निंग वाई डूइंग' पर फोकस किया जा रहा है। इससे बच्चों में सीखने की दर बढ़ेगी और उनमें क्रियेटिविटी की प्रवृति का विकास होगा। बच्चों में रचनात्मक दक्षता का विकास किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरैक्टिव माहौल बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों को खिलौनों के साथ-साथ हर एक चीज की जानकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से बताने का प्रयास होगा।

गतिविधि बॉक्स से बच्चों को आसान लगेगा विज्ञान व गणित

आईआईटी गांधीनगर के सेंटर ऑफ क्रियेटिव लर्निंग द्वारा छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए गतिविधि बॉक्स तैयार किया गया है। शिक्षक आकाश आनंद ने बताया कि गतिविधि बॉक्स में विज्ञान और गणित से जुड़ी दो सौ से अधिक गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों को बनाने में कागज व गत्ते का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि हमें गतिविधि के माध्यम से कई ऐसी चीजें बताई गयी जो आज तक हमने नहीं सीखी। इसे कक्षा में बच्चों से करवाया जाए तो उन्हें विज्ञान और गणित विषय आसान लगेगा और समझ में भी तुरंत आएगा।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 23.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

अभियान चला एक लाख स्टूडेंट्स को दिलाया जाएगा शिक्षा ऋण

पिछले साल लक्ष्य नहीं हो सका था पूरा, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक करने का दिया निर्देश

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

इस साल 2022-23 में एक लाख छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से शिक्षा ऋण देने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में जागरुकता अभियान चलाएं। स्टूडेंट और अभिभावकों को शिक्षा ऋण के बारे में पूरी जानकारी दें। 2021-22 में 75 हजार स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था, इसमें 66 हजार 349 यानी 88.5 प्रतिशत को 1896 करोड़ शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए। हालांकि इसके पहले कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहने से लक्ष्य का 50 प्रतिशत से भी कम स्टूडेंट को शिक्षा ऋण दिलाए जा सके थे। इस साल सबसे कम शिवहर 473 स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य रखा है। गया में 5266, भागलपुर 3298 और मुजफ्फरपुर में 4414 छात्रों को शिक्षा ऋण देना है।

शिक्षा वित्त निगम बना कर राज्य सरकार ऋण दे रही

बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने में आनाकानी के बाद लगभग 2 साल से राज्य सरकार शिक्षा वित्त निगम बना कर स्टूडेंट को ऋण दे रही है। सरकार शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से छात्रों को 4 प्रतिशत और छात्राओं व दिव्यांग स्टूडेंट को 1 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 4 लाख रुपए तक ऋण दिलाती है। विभिन्न तकनीकी संस्थानों के साथ सामान्य कोर्स के लिए भी छात्र शिक्षा ऋण ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सरकार ने कई बार कहा है कि शिक्षण संस्थानों से पास होने के बाद रोजगार मिलने पर आसानी से ऋण चुकाए। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में सरकार लोन माफ भी कर सकती है।

मैट्रिक-इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ

राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ का प्रावधान है। लेकिन बिहार से पड़ोसी राज्यों उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड के लगभग चार दर्जन प्रखंडों से पास करने वाले बिहार के निवासी स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत हर संकाय के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, एमबीए, बीसीए, पत्रकारिता सहित लगभग सभी उच्च शिक्षण के लिए शिक्षा ऋण लिया जा सकता है। 2 अक्तूबर 2016 से जब यह योजना शुरू हुई तो बैंक के माध्यम से लोन दिलाना था। एक अप्रैल 2018 से अब तक 2 लाख 6 हजार 320 आवेदक स्टूडेंट को 5599.64 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें 1 लाख 64 हजार 573 आवेदकों को 2607.31 करोड़ की राशि मिल चुकी है।

ऋण वापसी कोर्स पूरा होने के बाद 2 लाख तक के ऋण 60 मासिक किस्तों में और 2 लाख से अधिक ऋण को अधिकतम 84 किस्तों में वापस किया जा सकता है। अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी।

योजना से जुड़ने के लिए
ww.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर लॉगइन किया जा सकता है।

इस साल एक लाख स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देना है। लक्ष्य पाने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का जिलों को निर्देश दिया गया है। अभिभावकों को भी योजना की जानकारी देने के लिए कहा गया है। पिछले साल 75 हजार में 66 हजार से अधिक को ऋण स्वीकृत हुए हैं।
-सजन आर, नोडल पदाधिकारी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 23.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	409
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	126
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	41
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,48,08,913
⇒ कम से कम एक डोस	7,10,50,309
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,10,89,944

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

कतर
दक्षिण कोरिया
जापान
हॉग कॉग
यू.ए.ई.
सिंगापुर
बहरीन
न्यूजीलैंड
कनाडा
यू.एस.ए.
ऑस्ट्रेलिया
सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई
हैदराबाद
पुणे
चेन्नई
नागपुर
गुजरात
कोलकाता
वाराणसी
गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.